



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2005/चैत्र 16, 1927

No. 47]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2005/CHAITRA 16, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2005

सं. टीएएमपी/21/2005-आईजीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, कोच्चि पत्तन स्थित इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रचालन के लिए अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

प्रकरण सं. टीएएमपी/21/2005-आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल)

आदेश

आवेदक

(मार्च 2005 के 31 वें दिन पारित)

आईजीटीपीएल ने कथित रूप से, राजीव गाँधी कंटेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) में आवश्यक विकास, सुविधाओं में सुधार तथा कोच्चि पत्तन न्यास वल्लारपदम स्थित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसिपमेंट टर्मिनल के विकास, निर्माण, प्रचालन और प्रबंधन सहित, प्रचालन और प्रबंधन के अभिग्रहण के लिए 31 जनवरी 2005 को कोच्चि पत्तन न्यास के साथ लाइसेंस अनुबंध (एलए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रकरण आरजीसीटी में प्रचालन के लिए जो 1 अप्रैल 2005 से आरम्भ करने का प्रस्ताव है, अन्तरिम प्रशुल्क निर्धारण करने के लिए आईजीटीपीएल से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. आईजीटीपीएल ने आरजीसीटी के प्रचालन के लिए अनुमानित लागत / प्रक्षेपित निवेश की स्थिति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में कोई लागत विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। आईजीटीपीएल ने सीओपीटी के दरमान में कंटेनर संबंधी प्रचालन के लिए निर्धारित वर्तमान प्रशुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। चूंकि आरजीसीटी में प्रचालन शीघ्र ही आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है, इसने इस प्राधिकरण से प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था को 1 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005 तक की अवधि के लिए एक अन्तरिम उपाय के रूप में अनुमोदित करने और अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। इसने स्वीकार किया है कि वह प्रचालन की लागत और निवेश के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव 2005 से पहले दाखिल कर देगा।

3. आईजीटीपीएल ने सीओपीटी, कोचीन स्टीमर एजेंट्स एसोसियेशन, कस्टम हाऊस एजेंट्स एसोसियेशन कोचीन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कन्टेनर शिपिंग लाइनर्स एसोसियेशन और भारतीय नौवहन निगम से प्राप्त पत्रों की प्रतियाँ जिसमें, प्रस्तावित अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था के लिए अपनी सहमति व्यक्त की गई है, इस प्राधिकरण को भेजी हैं।

4. प्रशुल्क के सार्थक निर्धारण के लिए प्रचालन का निवेश और लागत विवरण आवश्यक होते हैं। इस प्रकरण में इस प्रकार का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि सीओपीटी के दरमान का निर्धारण पत्तन द्वारा प्रतिनिधित्व लागत स्थिति पर विचार करते हुए किया गया था, जो निजी प्रचालक के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता। निजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इस प्राधिकरण को तब यह बहुत अच्छा लगता जब प्रचालक टीएएमपी के पास समय रहते चला आता ताकि निजी प्रचालक द्वारा

सुविधाओं के अंतिम अधिग्रहण से पहले प्रशुल्क का निर्धारण हो चुका होता। चूंकि प्रचालन का आरम्भ 1 अप्रैल 2005 से किए जाने की सूचना है और इस बात को मानते हुए कि सीओपीटी तथा पत्तन उपयोगकर्ताओं के संबंधित प्रतिनिधि निकायों ने प्रस्तावित अंतरिम उपाय को अपनी-अपनी सहमति दे दी है, यह प्राधिकरण कुछ पहल करना चाहेगा। इस आशय से की प्रचालन 1 अप्रैल 2005 से जारी रहें यह प्राधिकरण आईजीटीपीएल द्वारा उसके प्रचालन के लिए 1 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005 तक 3 महीनों की अवधि के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में कंटेनर प्रचालनों के लिए सीओपीटी के वर्तमान दरमान को अपनाने के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान करता है। सीओपीटी के दरमान में निर्धारित प्रासंगिक सशर्तताएँ आईजीटीपीएल के मामले में भी, अंतरिम प्रशुल्क के प्रचालन के दौरान लागू होंगी।

5.1. अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के लिए अनुमोदन इस शर्त पर है कि आईजीटीपीएल निर्धारित प्रपत्र में 30 अप्रैल 2005 तक एक व्यापक प्रस्ताव दाखिल करेगा। ऐसा करते समय वह सभी सहायक प्रासंगिक विवरणों के सहित हाल ही में घोषित, संशोधित प्रशुल्क निर्धारण मार्गदर्शियों को ध्यान में रखेगा ताकि टीएएमपी आंतरिक जॉच-पड़ताल तथा प्रासंगिक पक्षों के साथ सामान्य परामर्श के बाद 30 जून तक इस विषय में अपना निर्णय ले ले।

5.2. यदि इस प्राधिकरण द्वारा 30 जून 2005 तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अब अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था 1 जुलाई 2005 के बाद भी अंतिम दरों के निर्धारण तक जारी रहेगी और अंतरिम दरों में 10 प्रतिशत की दर से समान कटौती की जायेगी।

6. साधारणतया इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें कुछ समय अंतराल देने के बाद लागू की जाती हैं। चूंकि आईजीटीपीएल अपना प्रचालन 1 अप्रैल 2005 से आरम्भ कर देगा, इस प्रकरण में अनुमोदित दरों को लागू करने के लिए समय अंतराल को छोड़ना आवश्यक हो गया है। आईजीटीपीएल के लिए अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से प्रभाव में आ जायेगी।

अ० ल० बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/05-असा०]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2005

No. TAMP/21/2005-IGTPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves an interim tariff arrangement for operations of India Gateway Terminal Private Limited at the Cochin Port, as in the Order appended hereby.

Case No. TAMP/21/2005 - IGTP

India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) - - - -

Applicant

ORDER

(Passed on this 31st day of March 2005)

The IGTP has reportedly entered into a Licence Agreement (LA) with the Cochin Port Trust (COPT) on 31 January 2005 for taking over the operation and management including necessary development, modification of facilities of the Rajiv Gandhi Container Terminal (RGCT) and development, construction, operation and management of International Container Transshipment Terminal at Vallarpadam in Cochin Port Trust. This case relates to a proposal received from the IGTP for fixation of interim tariff for its operation at RGCT which is proposed to commence from 1 April 2005.

2. The IGTP has not filed any cost details in the prescribed format indicating the estimated cost/ projected investment position for operating the RGCT. The IGTP has proposed to levy the existing tariff prescribed in the Scale of Rates of the COPT for container related operations. Since operation at the RGCT is proposed to be commenced shortly, it has requested this Authority to approve and notify the proposed tariff arrangement as an interim measure for a period of three months from 1 April 2005 to 30 June 2005. It has agreed to file a detailed proposal based on their cost of operation and investment before June 2005.

3. The IGTPPL has also forwarded letters from the COPT, the Cochin Steamer Agents' Association, Custom House Agents' Association, Cochin Chamber of Commerce and Industry, Container Shipping Lines Association and the Shipping Corporation of India giving their consent to the proposed interim tariff arrangement.

4. For meaningful fixation of tariff, investment and cost details of operation are essential. No such details are made available in this case. It may be relevant to mention that the Scale of Rates of the COPT was fixed taking into consideration the cost position reflected by the port which may not be relevant for the private operator. As a part of privatisation process, this Authority would have very much liked the operator to approach TAMP well in time so that tariff could have been fixed before the final taking over of the facilities by the private operator. Since the operation is reported to be commencing from the 1 April 2005 and also recognising that the COPT and concerned representative bodies of port users have given their consent to the proposed interim measure, this Authority would like to take some initiative. In order that operations continue from 1 April 2005, this Authority approves adoption of the existing Scale of Rates of COPT for container operations by IGTPPL for its operation as an interim measure for a period of three months from 1 April 2005 to 30 June 2005. The relevant conditionalities prescribed in the Scale of Rates of COPT will apply in the case of IGTPPL also during the operation of interim tariff.

5.1. The approval for the interim tariff arrangement is subject to the IGTPPL filing a comprehensive proposal in the prescribed format bearing in mind the revised guidelines for tariff fixation announced recently alongwith all the relevant supporting details latest by 30 April 2005, so that TAMP can decide by 30 June 2005 after internal scrutiny and usual consultation with relevant parties.

5.2. If the final Order cannot be passed by this Authority by 30 June 2005, then the interim tariff arrangement approved now will continue beyond 1 July 2005 till fixation of final rates subject to a uniform reduction in the interim rates by 10%.

6. Ordinarily, the rates approved by this Authority are implemented after allowing a lead time. Since IGTPPL will commence operation from 1 April 2005, it is necessary to waive the lead time for implementation of the approved rates in this case. The interim tariff arrangement approved for IGTPPL shall come into effect from 1 April 2005.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT. III/IV/143/05-Exty.]